tv भारतवर्ष
सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

मिचेल स्टार्क की उपलब्धता अभी भी अनिश्चित

Page-04

मोहनलाल की 'दृश्यम 3' पोस्टपोन, अब 21 मई को रिलीज़

Page-05

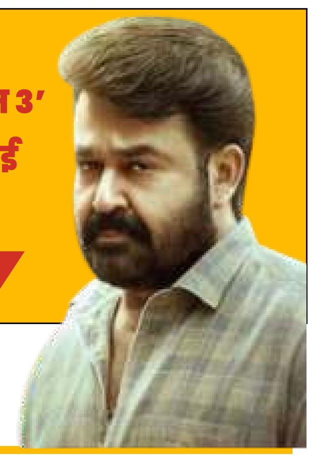

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ट्रम्प-मोदी की बातचीत

अंतर्राष्ट्रीय, टीवी भारतवर्ष

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में अहम बातचीत हुई। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी।बताया गया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की, खासकर होर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया, जो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम है।इस बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने ईरान की शर्तों के मुताबिक युद्ध को जल्द समाप्त करने पर सहमति जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ को गुप्त रूप से यह संदेश दिया है कि सुप्रीम लीडर ने वार्ता के लिए हरी झंडी दे दी है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में कूटनीतिक प्रयास तेज हो सकते हैं।

कोलंबिया में एयरफोर्स का हरक्यूलिस C-130 विमान क्रैश

कोलंबिया में सोमवार को एयरफोर्स का हरक्यूलिस C-130 विमान टेक-ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भीषण हादसे में अब तक 66 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हैं और 4 सैनिक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।समाचार एजेंसी AFP के अनुसार, मृतकों में 58 सैनिक, 6 वायुसेना कर्मी और 2 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। यह हादसा पेरू सीमा के पास दक्षिणी अमेजन क्षेत्र के प्यूर्टो लेगुइजामो में हुआ। रक्षा मंत्री पेद्रो सांचेज ने बताया कि विमान रनवे से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। विमान में कुल 125 लोग सवार थे, जिनमें 114 सैनिक और 11 क्रू मेंबर शामिल थे। सेना ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है।राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए इसे बेहद गंभीर घटना बताया। उन्होंने कहा कि जवानों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए सेना को आधुनिक संसाधनों से लैस किया जाएगा।

लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं
महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी

राष्ट्रीय, टीवी भारतवर्ष

केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में दो अहम बिल पेश किए जा सकते हैं।सरकार महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्तों में बदलाव करने की योजना बना रही है। प्रस्ताव के अनुसार, लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने एनडीए और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की है। अगर व्यापक सहमति बनती है, तो बिल इसी सप्ताह संसद में पेश हो सकते हैं।गौरतलब है कि 2023 में महिला आरक्षण कानून संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पारित हुआ था, जिसमें प्रावधान था कि आरक्षण नई जनगणना के बाद लागू होगा। अब सरकार नई जनगणना का इंतजार करने के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर प्रक्रिया को तेज करने पर विचार कर रही है।इन प्रस्तावित बिलों में एक 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन से जुड़ा होगा, जबकि दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव से संबंधित होगा। इन्हें पास कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा, इसलिए सरकार विपक्ष का समर्थन जुटाने में लगी है। आरक्षण के प्रस्तावित ढांचे में एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के भीतर हिस्सा मिलेगा, लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान फिलहाल शामिल नहीं है। इसी मॉडल को राज्यों की विधानसभाओं में भी लागू करने की योजना है।सरकार ने कई क्षेत्रीय दलों से चर्चा कर ली है, लेकिन कांग्रेस के साथ बातचीत अभी बाकी है। सहमति बनने पर यह बिल जल्द ही संसद में पेश किए जा सकते हैं।

- **केंद्र सरकार महिला आरक्षण (33%) को जल्द लागू करने के लिए नए बिल लाने की योजना बना रही है, जिसमें लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव शामिल है।**
- **सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर प्रक्रिया तेज करना चाहती है, लेकिन बिल पास कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत जरूरी है, इसलिए विपक्ष का समर्थन अहम होगा।**

पश्चिम एशिया संकट पर पीएम मोदी की चेतावनी
देश को रहना होगा तैयार

राष्ट्रीय, टीवी भारतवर्ष

नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव को लेकर राज्यसभा में चिंता जताते हुए कहा कि यदि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष जारी रहता है, तो इसके गंभीर वैश्विक परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला समय देश के लिए बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है और इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी होगा।प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट का असर भारत पर भी दिखाई देने लगा है। व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं और गैस, तेल तथा उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर दबाव बढ़ रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय जहाज और क्रू भी फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से वे पश्चिम एशिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से लगातार संपर्क में हैं।एक दिन पहले लोकसभा में भी प्रधानमंत्री ने इसी मुद्दे पर बात करते हुए कहा था कि इस संघर्ष का असर लंबे समय तक बना रह सकता है, इसलिए देश को पहले से तैयार रहना होगा। उन्होंने कोरोना काल का उदाहरण देते हुए कहा कि एकजुटता से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि वे गरीबों और श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना का लाभ सुचारु रूप से जारी रखें। साथ ही उन्होंने कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। न्होंने जोर देकर कहा कि संकट के बावजूद देश की तेज आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
धर्म बदलने पर खत्म होगा SC दर्जा

- सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म अपनाने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति (SC) दर्जा और उससे जुड़े कानूनी अधिकार स्वत: खत्म हो जाएंगे।

राष्ट्रीय, टीवी भारतवर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) दर्जे को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यह दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों तक ही सीमित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इन धर्मों के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है, तो उसका SC दर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगा।कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा ईसाई या अन्य धर्म में धर्मांतरण करने पर वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। इस फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि धर्म परिवर्तन के बाद संबंधित व्यक्ति SC/ST अत्याचार निवारण कानून के तहत शिकायत दर्ज कराने का अधिकार भी खो देता है।सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले दिए गए फैसले को सही ठहराया। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि जो लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं और उसका पालन करते हैं, वे SC दर्जा बरकरार नहीं रख सकते।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने दोहराया कि SC का दर्जा धर्म से जुड़ा हुआ है और यह केवल हिंदू, सिख और बौद्ध समुदायों के लिए मान्य है। ऐसे में किसी अन्य धर्म को अपनाने पर यह संवैधानिक

गाजियाबाद पुलिस का बड़ा खुलासा
पाकिस्तान के लिए जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश, 22 गिरफ्तार

राष्ट्रीय, टीवी भारतवर्ष

गाजियाबाद पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए नौशाद अली उर्फ लालू को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले तीन महीनों से गांव नचौली में एक पेट्रोल पंप पर पंचर की दुकान चला रहा था और उसी की आड़ में जासूसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था।पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह के सरगना सुहेल समेत अब तक कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस कार्रवाई में नौशाद के अलावा मथुरा की एक महिला और एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों को इस नेटवर्क से जोड़ने का काम सुहेल ने ही किया था।जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह रेलवे स्टेशनों और सुरक्षा बलों के ठिकानों की तस्वीरें और वीडियो बनाकर व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए पाकिस्तान भेजता था। इसके बदले उन्हें हर फोटो के लिए 4 से 6 हजार रुपये तक दिए जाते थे।चौंकाने वाली बात यह है कि गिरोह ने दिल्ली और हरियाणा के कई रेलवे स्टेशनों पर गुप्त कैमरे भी लगा रखे थे, जिनकी लाइव स्ट्रीमिंग पाकिस्तान में बैठे लोगों तक पहुंचाई जा रही थी।पुलिस के अनुसार, यह नेटवर्क देशभर में करीब 50 सोलर कैमरे लगाने की योजना पर काम कर रहा था,

जिनमें से कुछ पहले ही इंस्टॉल किए जा चुके थे। सोनीपत और दिल्ली में लगाए गए कैमरों को बरामद कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।जांच में यह भी सामने आया कि नौशाद मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और उसे कोलकाता से बुलाकर फरीदाबाद में यह दुकान खुलवाई गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और इसके अन्य कनेक्शनों की तलाश जारी है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में पश्चिम एशिया युद्ध की रणनीति तैयार की

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने CCS की बैठक में नागरिकों की खाद्य, ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। सरकार ने प्रभावों से निपटने हेतु मंत्रियों और सचिवों का समन्वय समूह गठित किया।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सभी सेना प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) प्रमुख, रक्षा सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा हालात का आकलन करना और देश की रणनीतिक तैयारियों की समीक्षा करना था। जानकारी के अनुसार, पश्चिम एशिया में युद्ध फिलहाल चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, और भारत सरकार इस क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों पर कड़ी निगरानी रख रही है। इसी बीच, अमेरिका के युद्ध उप सचिव एलब्रिज कोल्बी भारत में हैं और वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। यह दौरा वर्तमान तनाव की वैश्विक और द्विपक्षीय प्रभावों का आकलन करने के लिए किया गया है। वहीं, सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) ने भी पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की। बैठक में खाद्य, ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा सहित आम नागरिक की आवश्यकताओं की उपलब्धता का विस्तृत आकलन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के बाद कहा कि यह संघर्ष एक बदलती हुई स्थिति है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकार के सभी अंगों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि आम नागरिकों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। उन्होंने मंत्रियों और सचिवों का एक समूह गठित करने का निर्देश भी दिया, जो इस संघर्ष के प्रभावों से निपटने के लिए समर्पित रूप से काम करेगा। सीसीएस की बैठक में आवश्यक वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मध्यम और दीर्घकालिक उपायों पर भी चर्चा हुई। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। इस पर भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का भी व्यापक आकलन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि देश की सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में CCS आवश्यक कदम उठाएगी। इसमें खाद्य, ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा के अलावा आम नागरिक की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुरूप, देश भर में सभी संबंधित विभागों और मंत्रालयों को सक्रिय होकर काम करना होगा ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

कम वजन वाले सिलेंडर पर अफवाहों को पेट्रोलियम मंत्रालय ने खारिज किया

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और एलपीजी आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत सरकार ने घरेलू और व्यावसायिक गैस आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। तेल विपणन कंपनियों (OMC) द्वारा 14.2 किलोग्राम के सिलेंडरों को कम वजन वाले सिलेंडरों में बदलने की खबरों को पेट्रोलियम मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इसे पूरी तरह अफवाह करार दिया और कहा कि "किसी भी अटकल पर कोई टिप्पणी या स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता।"हालांकि, रिफाइनरियों ने सरकार को इस मामले पर एक प्रस्ताव भेजा है और अधिकारियों ने कहा कि इस पर विचार चल रहा है। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा।सरकार ने आपूर्ति दबाव को कम करने और गैस वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम तेज कर दिए हैं। इसके तहत शहरों में पाइपलाइन गैस परियोजनाओं (सीएनजी/पीएनजी) के आवेदन तेजी से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) ने अपने कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे शहर गैस वितरण (सीजीडी) के सभी आवेदन केवल 10 दिनों में निपटाएं।इसके अलावा, बड़े शहरों और शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक एलपीजी उपभोक्ताओं को भी एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए रसोई गैस की पाइपलाइन (पीएनजी) की ओर स्थानांतरित करने की सलाह दी गई है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को एलपीजी की निरंतर और संतुलित आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

ट्रंप की 'शांति वार्ता' का दावा ईरान ने किया खारिज
बहरीन और कुवैत में सुरक्षा अलर्ट जारी

भारतीय रेलवे ने टिकट रिफंड नीति में बड़े बदलाव किए

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

भारतीय रेलवे ने मंगलवार को अपनी टिकट और रिफंड नीति में व्यापक बदलाव की घोषणा की, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से टिकटों की कालाबाजारी को रोकना और यात्रियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करना है। नए नियमों के तहत अब यात्रियों को निर्धारित प्रस्थान समय से आठ घंटे से कम समय पहले आरक्षित टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं, यात्रा से 24 घंटे से 8 घंटे पहले रद्द करने पर 50 प्रतिशत रिफंड और 72 घंटे से 24 घंटे पहले रद्द करने पर 75 प्रतिशत रिफंड प्रदान किया जाएगा। इससे पहले, यात्रियों को यात्रा से 72 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर पूरा रिफंड मिलता था।रेलवे ने ऑफलाइन टिकट धारकों के लिए टिकट रद्द करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। अब यात्री किसी भी रेलवे स्टेशन से अपना टिकट रद्द कर सकते हैं, चाहे वह टिकट मूल रूप से किसी भी स्टेशन से बुक किया गया हो। इसके अतिरिक्त, यात्रियों को अब टिकट पर उल्लिखित प्रस्थान स्टेशन के बाद किसी भी स्टेशन से ट्रेन में सवार होने की अनुमति मिलेगी। मोबाइल एप्लिकेशन में भी बोर्डिंग पॉइंट अपडेट करने का विकल्प अब उपलब्ध है। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे ने यह भी निर्णय लिया है कि वे ट्रेन प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक अपने कोच की श्रेणी बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि थर्ड एसी जैसी निचली श्रेणी में यात्रा कर रहे यात्रियों को सीट उपलब्ध होने पर फर्स्ट एसी जैसी उच्च श्रेणी में जाने का विकल्प मिलेगा। यह सुविधा केवल रेलवे के आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से उपलब्ध होगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ये बदलाव न केवल कालाबाजारी को रोकने में मदद करेंगे, बल्कि यात्रियों को अधिक नियंत्रण और सुविधा भी प्रदान करेंगे। टिकट रद्द और कोच अपग्रेड जैसे विकल्पों से यात्रियों की यात्रा अनुभव को और सहज बनाने में मदद मिलेगी।

इजरायल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में सैन्य कार्रवाई शुरू की
लिटानी नदी तक सीमा बढ़ाने की तैयारी

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

मध्य पूर्व में ईरानी युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बढ़ रही है। लगातार हमलों और बढ़ती हताहतों के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक प्रभाव भी बढ़ रहे हैं। वाशिंगटन और तेहरान के विरोधाभासी बयानों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। अमेरिका कूटनीतिक पहल की ओर इशारा कर रहा है, जबकि ईरान ने ऐसी दावों को खारिज कर दिया है, जिससे दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और गहरा गया है। इस संघर्ष का प्रत्यक्ष सैन्य असर ही नहीं, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव भी स्पष्ट हो रहे हैं। ऊर्जा बाजार अस्थिर हैं, वैश्विक तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर यातायात बाधित होने की आशंकाएं विश्व स्तर पर आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं। सुरक्षा गठबंधनों की भी परीक्षा चल रही है, क्षेत्रीय शक्तियां रक्षात्मक उपाय बढ़ा रही हैं और वैश्विक शक्तियां तनाव बढ़ने के संकेतों पर नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच, इजरायल के वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने कहा कि इजरायल को लेबनान के साथ अपनी सीमा को दक्षिणी हिस्से में स्थित लिटानी नदी तक बढ़ा देना चाहिए। इसके साथ ही, इजरायली सैनिकों ने उस क्षेत्र में पुलों और घरों को नष्ट कर दिया, जिससे सैन्य कार्रवाई और तेज हुई। स्मोट्रिच ने एक रेडियो कार्यक्रम में कहा कि लेबनान में सैन्य अभियान का अंत एक नई

वास्तविकता के साथ होना चाहिए, जिसमें हिज़्बुल्लाह का निर्णय और इजरायल की सीमाओं में बदलाव दोनों शामिल हों। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में छोटी दक्षिणपंथी पार्टी के नेता स्मोट्रिच अक्सर आधिकारिक इजरायली नीति से अलग टिप्पणियां करते हैं। रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज़ ने भी इस महीने शुरुआत में भूमि पर कब्ज़ा करने के संकेत दिए थे। इजरायल ने लिटानी नदी के ऊपर सभी पुल नष्ट कर दिए हैं ताकि दक्षिण और उत्तर लेबनान के बीच संपर्क कट जाए। लेबनान के एक कस्बे के मेयर हन्ना अमील के अनुसार अब सामान लाने के लिए हफ्ते में केवल एक-दो बार लेबनानी सेना के काफिले की मदद ली जा रही है। संघर्ष के मानवीय पहलू भी गंभीर हैं। लेबनान और ईरान के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। बिजली नेटवर्क और शहरी बुनियादी ढाँचे पर हमले नागरिक जीवन को सीधे प्रभावित कर रहे हैं।

ट्रम्प की ईरान वार्ता घोषणा से पहले संदिग्ध ट्रेडिंग
वैश्विक बाजारों में बढ़ी चिंता

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

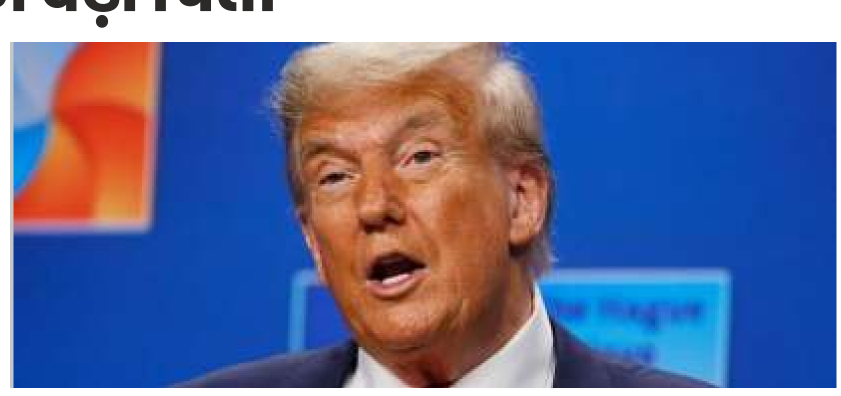

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ईरान के साथ संभावित सकारात्मक वार्ता की घोषणा से ठीक पहले वैश्विक वित्तीय बाजारों में हुए असामान्य और बड़े पैमाने पर ट्रेड ने बाजार की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सौदों के समय और प्रकृति को लेकर अब संभावित अंदरूनी जानकारी (इंसाइडर ट्रेडिंग) के आरोपों की जांच तेज हो गई है।रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रम्प की सार्वजनिक घोषणा से कुछ मिनट पहले ही व्यापारियों ने तेल की कीमतों में गिरावट और शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद में बड़े दांव लगाए। जब बाद में ट्रम्प ने ईरान के साथ "सार्थक बातचीत" और सैन्य कार्रवाई में अस्थायी विराम की बात कही, तो तेल की कीमतों में गिरावट आई और शेयर बाजार में उछाल दर्ज किया गया—जो पहले किए गए सौदों के अनुरूप था।फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क समयानुसार सुबह 6:49 से 6:50 बजे के बीच ब्रेंट और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड वायदा में लगभग 580 मिलियन डॉलर के सौदे किए गए। करीब 6,200 अनुबंधों से जुड़े ये लेन-देन ट्रम्प के बयान से लगभग 15 मिनट पहले हुए थे। इन सौदों का उद्देश्य स्पष्ट रूप से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट पर दांव लगाना था, जिसके तुरंत बाद बाजार में यही रुझान देखने को मिला।इसी दौरान, ट्रेडिंग वॉल्यूम में असामान्य वृद्धि दर्ज की गई और एसएंडपी 500 वायदा में तेजी शुरू हो गई। यह संकेत देता है कि विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में एक समन्वित रणनीति के तहत निवेश किया गया, मानो किसी बड़े भू-राजनीतिक घटनाक्रम की पूर्व जानकारी हो। शाम 4:35 बजे, ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दो दिनों में "बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत" हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरानी ऊर्जा ढांचे पर संभावित सैन्य हमलों को पांच दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिससे तनाव कम होने के संकेत मिलते हैं। इसके कुछ ही मिनट बाद, शाम 4:53 बजे, ट्रम्प ने अपने संदेश का संशोधित संस्करण साझा किया, जिसमें तकनीकी त्रुटियों को सुधारा गया, लेकिन मूल दावे—वार्ता और सैन्य कार्रवाई पर विराम—को बरकरार रखा गया। हालांकि, ईरानी अधिकारियों ने ऐसी किसी भी बातचीत से इनकार किया है, जिससे इस पूरे घटनाक्रम पर और अधिक संदेह गहरा गया है।

संपादक की कलम से

पर्यावरण संरक्षण एक गंभीर और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। औद्योगीकरण, शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता में कमी जैसी समस्याएँ तेजी से बढ़ रही हैं, जो मानव जीवन के लिए खतरा बनती जा रही हैं।वायु प्रदूषण आज महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक फैल चुका है। कारखानों से निकलने वाला धुआँ, वाहनों की बढ़ती संख्या और पेड़ों की कटाई ने हवा की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसी प्रकार जल स्रोत भी प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे पीने योग्य पानी की कमी उत्पन्न हो रही है। नदियाँ, जो कभी जीवनदायिनी मानी जाती थीं, आज गंदगी और रसायनों से भरती जा रही हैं।पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। छोटे-छोटे प्रयास भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे—पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, पानी और बिजली की बचत करना आदि। यदि हर व्यक्ति अपने स्तर पर जागरूक हो जाए, तो पर्यावरण की स्थिति में सुधार संभव है।शिक्षा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। बच्चों को शुरुआत से ही प्रकृति के महत्व के बारे में सिखाया जाए, ताकि वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बन सकें।सरकार को भी सख्त पर्यावरणीय नीतियाँ लागू करनी चाहिए और उनका पालन सुनिश्चित करना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम हो सके।अंततः, यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाते, तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए समय की मांग है कि हम सभी मिलकर पर्यावरण संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बनाएं और एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की दिशा में प्रयास करें।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में पेश किया 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में विकास और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है। कुल आवंटन का 21% 'ग्रीन बजट' के लिए, धूल-मुक्त सड़कें, बिजली आपूर्ति, जल प्रबंधन और गैर-अनुरूप क्षेत्रों पर बड़े निवेश शामिल हैं।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें कुल व्यय 1,03,700 करोड़ रुपये रखा गया। इस बजट में पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचे, शहरी विकास और प्रमुख क्षेत्रों में रिकॉर्ड आवंटन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसे भविष्योन्मुखी योजना बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के राज्यों में तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बजट के जरिए उनकी सरकार ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष 1 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया गया था, जबकि इस वर्ष इसे बढ़ाकर 1,03,700 करोड़ रुपये किया गया है। बजट का एक प्रमुख स्तंभ "ग्रीन बजट" है, जिसके लिए कुल आवंटन का 21 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया गया। रेखा गुप्ता ने कहा, "हम हर नीति और योजना को पर्यावरण के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। विकास और धरती माता के बीच संतुलन बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। यह दृष्टिकोण प्रधानमंत्री के 4S ढांचे—गति, कौशल, शक्ति और व्यापकता—के अनुरूप है।"बजट में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को 5,921 करोड़ रुपये और शहरी विकास एवं आश्रय परियोजनाओं के लिए 7,887 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारा लक्ष्य सुरक्षित सड़कें, जलवायु गलियारे और बेहतर संपर्क व्यवस्था सुनिश्चित करना है।" बिजली विभाग के लिए 3,942 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें ओवरहेड बिजली तार हटाने के लिए 200 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं। यमुना पार क्षेत्र के विकास के लिए 300 करोड़ रुपये और दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के लिए 787 करोड़ रुपये रखे गए हैं। शहर में धूल-मुक्त सड़कों के विकास के लिए 1,352 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 750 किलोमीटर सड़कों की 'एंड-टू-एंड रिकार्पेटिंग' की जाएगी।बजट में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 160 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पहली बार है कि गैर-अनुरूप (नॉन-कन्फॉर्मिंग) क्षेत्रों को बजट आवंटन में शामिल किया गया है। गैर-अनुरूप क्षेत्रों से तात्पर्य उन शहरी या औद्योगिक क्षेत्रों से है जो मौजूदा मास्टर प्लान, जोनिंग नियमों या भूमि उपयोग मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इसके अलावा, नजफगढ़ नाले के लिए 454 करोड़ रुपये और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलएएलएडी) के लिए 350 करोड़ रुपये रखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट दिल्ली की समग्र विकास योजनाओं को गति देगा और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट न केवल विकास को गति देगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और नागरिक जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्रीन बजट और बुनियादी ढांचे पर निवेश के साथ, दिल्ली को स्मार्ट और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का यह एक ठोस कदम माना जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान: किसानों की आय कई क्षेत्रों में तीन से आठ गुना बढ़ी

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण किसानों की आय केवल दोगुनी नहीं, बल्कि कई मामलों में तीन से आठ गुना तक बढ़ी है। यह जवाब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के पूरक प्रश्न के उत्तर में दिया। चौहान ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र ने विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं, जिनसे उनकी आमदनी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।वहीं, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का हवाला देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के कारण पेट्रोल-डीजल की कीमतें नियंत्रित रखी जा रही हैं। उन्होंने चेताया कि चुनाव खत्म होते ही देश को नई आर्थिक वास्तविकताओं का सामना करना होगा।भाजपा के सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पहले भी प्रतिकूल परिस्थितियों में देश को संभाल चुकी है और इस बार भी करेगी। उन्होंने लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान यह भी कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास' केवल नारा नहीं, बल्कि सरकार की विचारधारा है।वहीं, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में केवल 'सिलेंडर संकट' नहीं बल्कि 'सरेंडर संकट' भी है, जिसमें निर्णय अमेरिका द्वारा लिए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों को देश के नुकसान का कारण बताया।जम्मू-कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय सांसद अब्दुल रशीद शेख ने लोकसभा में घोषणा की कि वे अपने एक महीने का वेतन ईरान के उस स्कूल को दान करेंगे, जिस पर हमले में 100 से अधिक बच्चियों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि इस समय सरकार को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए।राज्यसभा में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि देशभर में 18,646 जन औषधि केंद्र संचालित हैं, जो किफायती दरों पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना की शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन 2014 तक केवल 80 केंद्र खोले गए थे।सांसद सुमित्रा बाल्मीक ने राज्यसभा में छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान डालने वाले विवाह और अन्य समारोहों में लाउड स्पीकर के उपयोग पर चिंता जताई और सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की।

बिहार सरकार ने स्कूल, पूजा स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मांस-मछली की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों, पूजा स्थलों और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के पास मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।सिन्हा ने बताया कि यह कोई नया नियम नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद कानून और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा, "हम मौजूदा कानून और नियमों को ही लागू कर रहे हैं। इसका पालन जनता और स्वास्थ्य के हित में है, और इससे स्वच्छता अभियान को भी मजबूती मिलेगी।"अधिकारियों ने स्कूलों, कॉलेजों, मंदिरों, मस्जिदों और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के आसपास चल रही दुकानों पर नजर रखी है। इन दुकानों को नियमों का उल्लंघन करते पाया गया है, जो सामाजिक सद्भाव और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित प्रतिबंध को सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाएगा और लाइसेंस धारक विक्रेताओं को भी कोई छूट नहीं दी जाएगी।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार व्यक्तिगत खान-पान की पसंद का सम्मान करती है, लेकिन सभी को सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए और दूषित या अस्वच्छ उत्पादों से सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डालना चाहिए।कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है। शहरी विकास और आवास विभाग ने रविवार को सभी नगर निकायों को निर्देश जारी किए हैं कि वैध लाइसेंस के बिना चल रही मांस और मछली की दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विभाग ने कहा कि कई दुकानें बिहार नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन करते हुए खुले और अस्वच्छ स्थानों पर संचालित हो रही हैं, जिससे कानून व्यवस्था, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।सरकार का कहना है कि यह

कदम केवल नियमों के पालन के लिए नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखा जा सके। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि यह नीति राज्य के नागरिकों और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

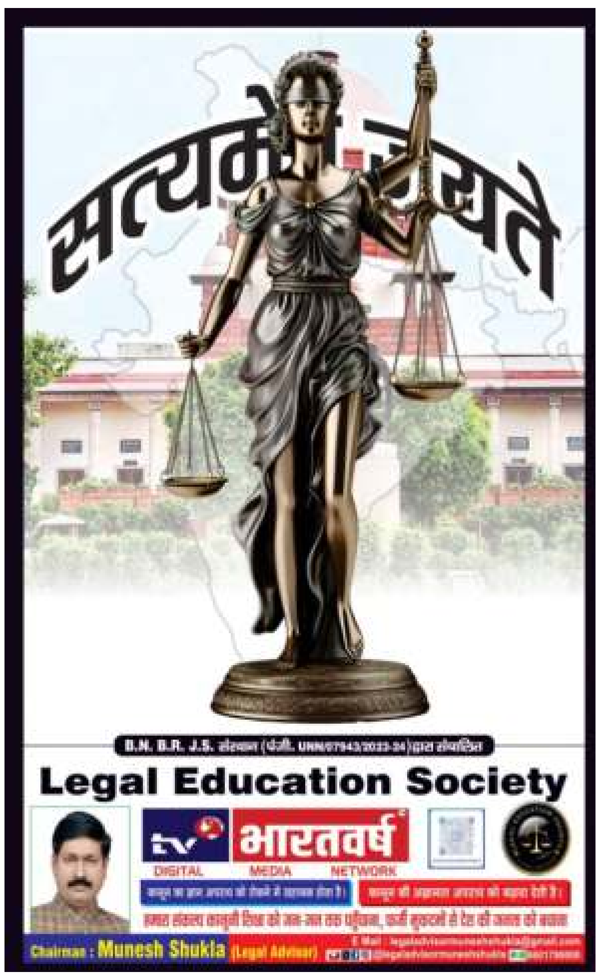

वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव कम होने और तेल की कीमतों में 14% गिरावट के कारण तेजी

भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव कम होने और कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के चलते दलाल स्ट्रीट में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। शुरूआती कारोबार में ही BSE Sensex 1,500 अंकों से अधिक उछल गया, जबकि Nifty 50 ने 22,800 के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर लिया।आज Sensex 1,516.08 अंक या 2.08 प्रतिशत बढ़कर 74,212.47 पर खुला, वहीं Nifty 50 365.8 अंक की बढ़त के साथ 22,878.45 पर कारोबार करने लगा। पिछले ट्रेडिंग सत्र में Sensex 72,696.39 और Nifty 50 22,512.65 पर बंद हुए थे।इसी तरह, व्यापक इंडेक्स भी हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। BSE Midcap Select Index शुरूआती सत्र में 363.43 अंक या 2.46 प्रतिशत की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था, वहीं BSE Smallcap Select Index 158.28 अंक या 2.31 प्रतिशत बढ़कर 7,18.79 पर पहुंचा। यह उछाल ऐसे समय आया है जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।शुरूआती कारोबार में बाजार की स्थिति (market breadth) सकारात्मक रही; NSE पर 189 शेयर गिरावट में रहे, जबकि 2,297 शेयरों में बढ़त दर्ज हुई। 58 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान ने कहा, "जब तक Nifty 22,800/Sensex 73,600 से नीचे ट्रेड करता रहेगा, तब तक कमजोरियों का दबाव बना रहेगा। नीचे की ओर बिकवाली 22,500/72,700 तक जा सकती है। अगर यह स्तर टूटता है, तो इंडेक्स 22,000/71,000 तक गिर सकता है। दूसरी ओर, अगर इंडेक्स 22,800/73,600 से ऊपर बना रहता है, तो यह 23,000-23,400/74,200-75,400 तक जा सकता है।"आज Gift Nifty, जो Nifty 50 के लिए शुरूआती संकेतक है, ने भी मजबूत सकारात्मक शुरूआत का संकेत दिया। यह पिछले बंद भाव 22,465 के मुकाबले 692.5 अंकों की बढ़त के साथ 23,157.50 पर खुला।विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने लगातार सत्रहवें दिन बिकवाली जारी रखी और 23 मार्च, 2026 को 10,414.23 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 12,033.97 करोड़ रुपये की खरीदारी करके इस बिकवाली को काफी हद तक संतुलित किया।एशियाई बाजारों में भी तेजीएशियाई शेयरों में भी आज तेजी देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में 14 प्रतिशत तक की गिरावट और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ईरान की ऊर्जा सुविधाओं पर प्रस्तावित हमलों को टालने का संकेत मुख्य कारण रहे। वॉल स्ट्रीट के रुख के अनुरूप, S&P 500 में 1.1 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जो युद्ध शुरू होने के बाद का सबसे अच्छा दिन था।जापान का Nikkei 225 353.51 अंक या 0.69 प्रतिशत बढ़कर 51,869 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि हांगकांग का Hang Seng 407.53 अंक या 1.67 प्रतिशत ऊपर था। दक्षिण कोरिया का Kospi 329.17 अंकों की बढ़त के साथ हरे निशान में था। शंघाई का SSE कंपोजिट इंडेक्स भी 36.06 अंक या 0.95 प्रतिशत बढ़कर सकारात्मक व्यापार संकेत दे रहा था।विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव में कमी और तेल की कीमतों में गिरावट से न सिर्फ भारतीय बाजार में मजबूती आई है, बल्कि निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। शुरूआती कारोबारी आंकड़े और बाजार की स्थिति इस बात का संकेत देती हैं कि यदि वैश्विक कारक स्थिर रहे, तो इंडेक्स आगामी दिनों में और तेजी दिखा सकते हैं।

काराबाओ कप फाइनल: मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल को 2-0 से हराकर जीती ट्रॉफी

काराबाओ कप फाइनल में मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल को 2-0 से हराकर इस सीजन की पहली ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मुकाबले के हीरो युवा खिलाड़ी निको ओ'रेल्ली रहे, जिन्होंने केवल चार मिनट के भीतर दो गोल करके टीम की जीत पक्की कर दी। इस जीत के साथ मैनचेस्टर सिटी का यह लीग कप में नौवां खिताब है और कोच पेप गार्डियोला के नेतृत्व में यह पांचवीं सफलता मानी जा रही है।मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। पहला हाफ संघर्षपूर्ण रहा, जिसमें गोलकीपर जेम्स ट्रैफर्ड ने अपने शानदार बचाव से आर्सेनल के कई हमलों को नाकाम किया। आर्सेनल ने मौके बनाए लेकिन गोल में बदलने में सफल नहीं हो पाए।दूसरे हाफ में मैनचेस्टर सिटी ने खेल पर बेहतर पकड़ बनाना शुरू किया। टीम ने आक्रमण की गति बढ़ाई और इसका फायदा निको ओ'रेल्ली को मिला। मैच के लगभग एक घंटे बाद उन्होंने गोलकीपर की गलती का लाभ उठाकर पहला गोल किया। इसके कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने दूसरा गोल भी कर दिया, जिससे मुकाबला लगभग सिद्ध हो गया। दूसरे गोल में टीम के खिलाड़ियों के बीच उत्कृष्ट तालमेल देखने को मिला, जिसमें सटीक पास और क्रॉस ने ओ'रेल्ली को आसान अवसर प्रदान किया।इसके बाद आर्सेनल के लिए वापसी मुश्किल हो गई। मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्ड ने खेल को पूरी तरह नियंत्रित किया और आर्सेनल को ज्यादा मौके नहीं दिए। आर्सेनल की टीम दबाव में दिखी और निर्णायक समय पर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस जीत के साथ मैनचेस्टर सिटी ने न केवल ट्रॉफी जीती, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाया।

आईपीएल 2026: आरसीबी को झटका
यश दयाल पर्सनल कारणों से पूरे सीजन से बाहर

मिचेल स्टार्क की उपलब्धता अभी भी अनिश्चित

आईपीएल 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने अपने प्री-सीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें फ्रेंचाइजी ने कई अहम संकेत दिए। कप्तान अक्षर पटेल और कोच हेमंग बदानी ने टीम की तैयारियों, रणनीति और चुनौतियों पर खुलकर बात की। सबसे बड़ा विषय रहा ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की उपलब्धता। अक्षर पटेल ने कहा कि टीम को अभी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) का इंतजार है। उन्होंने बताया कि स्टार्क अपनी फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण टीम के साथ जुड़ने में देरी कर रहे हैं। ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर भी टीम ने साफ किया कि केएल राहुल सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहे हैं। पिछले सीजन की सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में बात करते हुए अक्षर ने माना कि ओपनिंग में लगातार बदलाव टीम के लिए चुनौती रही थी। कोच हेमंग बदानी ने बताया कि पिछले साल कई खिलाड़ियों को आजमाया गया, जैसे अभिषेक पोरेल, जेक फ्रेजर-मैकगर्क और फाफ डुप्लेसिस, लेकिन चोट और उपलब्धता की वजह से संतुलन नहीं बना। इस बार टीम ने रणनीतिक चयन करते हुए पृथ्वी शॉ, बेन डकेट और पथुम निसांका को शामिल किया है ताकि ओपनिंग की समस्या स्थायी रूप से हल हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान अक्षर पटेल ने आईपीएल के 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि यह नियम हरफनमौला खिलाड़ियों के विकास में बाधा डालता है। रोहित शर्मा और हार्दिक पंड्या पहले भी इस नियम के खिलाफ अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स अब नए ओपनिंग संयोजन और मिचेल स्टार्क की उपलब्धता पर निर्भर रहकर आईपीएल 2026 में संतुलित और प्रतिस्पर्धात्मक शुरुआत करने की तैयारी कर रही है।

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 सीटें हमेशा के लिए खाली रहेंगी
जान गंवाने वाले दर्शकों की याद में लिया गया भावुक और ऐतिहासिक फैसला

आईपीएल 2026 के आगाज से पहले आरसीबी और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने एक भावुक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 सीटें हमेशा के लिए खाली रखी जाएंगी। यह कदम पिछले साल 4 जून 2025 को आरसीबी की पहली आईपीएल खिताबी जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले 11 लोगों की याद में उठाया गया है। उस दिन स्टेडियम के बाहर उत्सव मनाने आई भीड़ इतनी भारी थी कि नियंत्रण खो गया और एक दर्दनाक हादसा हो गया। 11 दर्शकों की इस दुर्घटना में मौत ने पूरे क्रिकेट जगत को झकझोर दिया और इसे खेल इतिहास के सबसे दुखद दिनों में गिना गया। इस घटना ने क्रिकेट प्रेमियों के बीच शोक और संवेदनशीलता की लहर पैदा की। इस भावुक घटना को याद करते हुए, आरसीबी और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने मिलकर फैसला लिया कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के एक प्रमुख स्टैंड की 11 सीटें हमेशा के लिए खाली रहेंगी। ये सीटें अब कभी आम दर्शकों की बिक्री में नहीं जाएंगी। चाहे आईपीएल के मैच हों या अंतरराष्ट्रीय मुकाबले, यह क्षेत्र हमेशा खाली रहेगा, ताकि यह एक स्थायी और दृश्यमान श्रद्धांजलि बन सके।क्लब और एसोसिएशन के अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय केवल मृतकों को सम्मान देने के लिए नहीं, बल्कि उनके परिवारों और पूरे क्रिकेट प्रेमी समुदाय को यह याद दिलाने के लिए भी है कि सुरक्षा और अनुशासन हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम खेल और दर्शकों की सुरक्षा के प्रति उनकी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। आरसीबी के प्रवक्ता ने कहा, "हम उन 11 बहादुर प्रशंसकों को याद करते हैं, जिन्होंने हमेशा हमारे साथ उत्सव मनाया। यह कदम उनके सम्मान में उठाया गया है। हर मैच में जब दर्शक इन सीटों को खाली देखेंगे, यह उन्हें याद दिलाएगा कि खेल का असली मज़ा सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ ही आता है।" क्रिकेट प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों ने इस कदम की सराहना की है। उनका कहना है कि यह न केवल एक संवेदनशील श्रद्धांजलि है, बल्कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता भी बढ़ाएगा। आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले यह फैसला न केवल भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दर्शकों और खिलाड़ियों दोनों के लिए सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक भी बन गया है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम अब इन 11 सीटों के माध्यम से हमेशा उन लोगों की याद दिलाता रहेगा, जिन्होंने अपने उत्साह में प्राण गंवा दिए।

भारतीय महिला टीम का साउथ अफ्रीका दौरा
बीसीसीआई ने टी20 टीम का किया ऐलान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) की महिला चयन समिति ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया है। दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी, जो भारतीय महिला टीम के लिए साउथ अफ्रीका दौरे का हिस्सा होगी। इस दौरे की शुरुआत 17 अप्रैल को डरबन से होगी, जबकि अंतिम मैच 27 अप्रैल को बेनोई में खेला जाएगा।बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया के अनुसार, भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर होंगी, जबकि स्मृति मंधाना टीम की उपकप्तान के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगी। टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संतुलन रखा गया है। इसमें शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। विकेटकीपर के तौर पर ऋचा घोष चुनी गई हैं, जबकि उमा छेत्री बैक-अप विकेटकीपर के रूप में टीम में जगह बनाएंगी।इस दौरे के लिए युवा ऑलराउंडर अनुष्का शर्मा को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। उनका चयन टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों विभागों में संतुलन बनाने के उद्देश्य से किया गया है। साथ ही, अनुभवी भारती फुलमाली भी टीम में लौट आई हैं। 31 वर्षीय फुलमाली ने पिछला टी20 इंटरनेशनल मैच 9 मार्च 2019 को गुवाहाटी में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उस मैच में इंग्लैंड महिला टीम मात्र एक रन से विजयी रही थी। टीम में कुल 15 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें कप्तान और उपकप्तान के अलावा शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल, काशवी गौतम, भारती फुलमाली, उमा छेत्री और अनुष्का शर्मा शामिल हैं। यह चयन समिति ने खिलाड़ियों की वर्तमान फॉर्म, फिटनेस और आगामी अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किया है। बीसीसीआई ने कहा है कि भारतीय महिला टीम का उद्देश्य इस सीरीज में जीत हासिल करना और टीम की सामूहिक क्षमता को मजबूत करना है।

38 लाख के ऑफर पर फंसा टेक एक्सपर्ट

करियर का कन्फ्यूजन

बेंगलुरु के एक 27 वर्षीय टेक एक्सपर्ट को बेंगलुरु में 38 लाख सालाना और दुबई में 4.8 लाख महीने का जॉब ऑफर मिला है. इस युवा की दुविधा ने सोशल मीडिया पर 'कमाई बनाम बचत' की नई बहस छेड़ दी है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दुबई के टैक्स फायदे और बचत की बात कही. (Photo: Pexels)

विदेश में नौकरी का मतलब अक्सर बेहतर सैलरी, टैक्स में छूट, आधुनिक लाइफस्टाइल और इंटरनेशनल एक्सपोजर से जोड़ा जाता है. दुबई जैसे शहर में अच्छी सैलरी के साथ टैक्स-फ्री इनकम, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षित माहौल और ग्लोबल वर्क कल्चर का अनुभव मिलता है. वहां प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ एक अलग तरह की लाइफस्टाइल भी मिलती है, जो कई युवाओं को आकर्षित करती है. वहीं, भारत में नौकरी करने का अपना अलग सुकून है. अपने परिवार के साथ रहना, सुख-दुख में उनके साथ खड़ा होना, अपने लोगों के बीच रहकर करियर बनाना- यह भावनात्मक मजबूती देता है. यहां खर्च, बचत और भविष्य की योजना को समझना आसान होता है, साथ ही परिवार का साथ जीवन के हर उतार-चढ़ाव में साथ देता है. इसी तरह के बेंगलुरु का एक 27 वर्षीय टेक्निकल एक्सपर्ट कंफ्यूजन में है, जिसे भारत और दुबई से मोटी सैलरी के दो ऑफर मिले हैं. अब उसके सामने सवाल है- बेहतर कमाई के लिए विदेश जाए या परिवार और स्थिर करियर ग्रोथ के लिए भारत में ही रहे? बेंगलुरु के एक 27 साल के टेक्निकल एक्सपर्ट ने इंटरनेट पर लोगों से सलाह मांगी है. उन्हें दो नौकरी के ऑफर मिले हैं- एक बेंगलुरु में 38 लाख रुपये सालाना का और दूसरा दुबई में 21,000 एईडी (लगभग 5.19 लाख रुपए) प्रति महीने का. फिलहाल वह 32 लाख रुपये सालाना कमा रहे हैं.

बोरियत से बचने के लिए बनाया 'किडनैप बटन'

आजकल सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ अजीबोगरीब और मजेदार वायरल होता रहता है. इसी बीच एक ऐसा पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान भी किया और हंसाया भी. मामला बेंगलुरु के टेक एक्सपर्ट का है, जिसने बोरियत भरी वीकेंड लाइफ से छुटकारा पाने के लिए अनोखा तरीका निकाला है कि लोग उसे मजाक में "खुद का किडनैप" कह रहे हैं.

दुल्हन को गोद में उठाया और बुरी तरह गिर गया दूल्हा

इंप्रेशन के चक्कर में हो गया 'डिप्रेशन'

शादी के पलों को यादगार बनाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते. आज के रील वाले जमाने में हर खास पल को कैद करने का जुनून बढ़ गया है.

दूल्हन की एंट्री से लेकर दूल्हे के डांस तक सबकुछ कैमरे में कैद होता है ताकि ये लम्हे हमेशा-हमेशा के लिए याद रह सकें. लेकिन कई बार यही यादगार बनाने की कोशिशें ऐसी गलती बना देती हैं, जिन्हें देखकर लोग हंसने लगते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ एक शादी में, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस वीडियो में दूल्हे का ओवर कॉन्फिडेंस उस पर भारी पड़ जाता है. हुआ यूं कि दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर स्टेज पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरा प्लान गड़बड़ा जाता है. वायरल क्लिप में दिखाई देता है कि दूल्हा जयमाला से ठीक पहले 'पुष्पा' फिल्म वाला फेमस स्टेप करके सबका ध्यान खींचने की कोशिश करता है.

महिला ने सिर्फ मोमबत्ती से कमाए 63 करोड़

चीन में 'टोटके' का धंधा

चीन की एक इन्फ्लुएंसर को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे 10 साल जेल की सजा हो सकती है.

क्योंकि, उसने डेकोरेटेड मोमबत्तियों को 'विश कैंडल्स' बताकर बेचा और 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीबन 63 करोड़ रुपये कमाए. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के तनावग्रस्त युवा ऑनलाइन अजीबोगरीब उत्पाद खरीदकर 'भावनात्मक और आध्यात्मिक सुकून' तलाश रहे हैं. ऐसे में वहां के युवा ऐसे टोटकों के झांसों में आसानी आ जा रहे हैं, जिनमें उन्हें ऐसे अपनी समस्याओं का समाधान नजर आता है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसे सामान जो वास्तविकता को विकृत कर सकते हैं और टोटकों के तौर पर अंधविश्वास भी फैलाते हैं, इनसे युवाओं को दूर रहने की जरूरत है. चीन में, कुछ युवा अपने प्रेम संबंध को फिर से जगाने की उम्मीद में, इन्फ्लुएंसर्स द्वारा बेची जाने वाली इच्छा पूरी करने वाली मोमबत्तियों के लिए भारी कीमत चुका रहे हैं. ली झूओफान नाम की एक इंफ्लुएंस ने रूसी रियलिटी शो 'द बैटल ऑफ साइकिक्स' में आने के बाद चीन के सोशल मीडिया पर 6 लाख से अधिक फॉलोअर्स बना लिए, जहां उन्होंने एक मोमबत्ती का इस्तेमाल करके कार के बूट में छिपे एक व्यक्ति का पता लगाया और दावा किया कि वह महसूस कर सकती हैं.

मोहनलाल की 'दृश्यम 3' पोस्टपोन, अब 21 मई को रिलीज़

सुपरस्टार के 66वें जन्मदिन पर दर्शकों को मिलेगा तोहफ़ा

मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'दृश्यम 3' आखिरकार पोस्टपोन हो गई है। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर खुद इस खबर की पुष्टि की और बताया कि फिल्म अब 2 अप्रैल 2026 की बजाय 21 मई 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। यह तारीख मोहनलाल के जन्मदिन से भी जुड़ी हुई है; 21 मई को सुपरस्टार 66 साल के हो जाएंगे, और इस साल यह उनके लिए विशेष अवसर बन जाएगा।'दृश्यम 3' के पोस्टपोन होने का फैसला ऐसे समय में आया है जब बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' शानदार प्रदर्शन कर रही है। वहीं, यश की 'टॉक्सिक' फिल्म भी पहले ही जून तक के लिए टल चुकी है। फिल्म उद्योग इस तरह का शेड्यूल बदलाव दर्शकों और सिनेमाघरों दोनों के लिए रणनीतिक रूप से उचित हो सकता है। मोहनलाल के इस पोस्टपोनमेंट का कारण फिलहाल आधिकारिक तौर पर तकनीकी और मार्केटिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि, अभिनेता ने सोशल मीडिया पर यह स्पष्ट किया कि फिल्म की क्वालिटी और दर्शकों को बेहतर अनुभव देने के लिए यह निर्णय लिया गया। उन्होंने फैंस से अपील की कि वे इस थोड़े से विलंब को समझें और फिल्म के रिलीज़ होने पर उसका पूरा आनंद लें।इस बीच, मोहनलाल ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुपरस्टार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई-जनरेटेड कंटेंट में अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल के खिलाफ 'पर्सनैलिटी राइट्स' की सुरक्षा की मांग की है। उनके वकीलों ने कहा कि आधुनिक डिजिटल तकनीक और AI के माध्यम से कलाकारों की छवि का अनुचित इस्तेमाल बढ़ रहा है, और इसके प्रभाव से व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रतिष्ठा पर गंभीर असर पड़ सकता है। अदालत में दाखिल याचिका में मोहनलाल ने स्पष्ट किया कि किसी भी डिजिटल या AI आधारित कंटेंट में उनका नाम, चेहरा या आवाज़ बिना अनुमति के इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में 'दृश्यम' फ्रेंचाइज़ी की अपनी खास पहचान है। पहली फिल्म ने 2013 में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी, और 'दृश्यम 2' ने उसी की सफलता को और बढ़ाया। 'दृश्यम 3' से दर्शकों को बड़ी उम्मीदें हैं, और पोस्टपोनमेंट के बावजूद फिल्म की चर्चा सोशल मीडिया और फिल्म फोरम में लगातार बनी हुई है।फिल्म उद्योग विशेषज्ञ मानते हैं कि मोहनलाल का यह कदम दोहरे उद्देश्य को दर्शाता है: एक ओर, फिल्म को सही समय और बड़े पैमाने पर प्रमोशन के साथ रिलीज़ करना, और दूसरी ओर, अपने डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। फिल्म के निर्माताओं ने पहले ही घोषणा की थी कि 'दृश्यम 3' को मलयालम के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में भी रिलीज़ किया जाएगा।फैंस के लिए यह अच्छी खबर है कि सुपरस्टार का जन्मदिन और फिल्म रिलीज़ अब एक ही दिन पर आ रही है। मोहनलाल के करीबी सूत्रों का कहना है कि यह दिन दर्शकों और उनके फैंस के लिए यादगार साबित होगा। पोस्टपोनमेंट के बावजूद फिल्म की कहानी, मोहनलाल की अभिनय कला और हाई-प्रोडक्शन वैल्यू दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचेगी।'दृश्यम 3' का यह विलंब बॉक्स ऑफिस की रणनीति और डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मोहनलाल का फोकस न केवल अपनी फिल्म की सफलता पर है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और AI के बढ़ते प्रभाव में अपनी पहचान को सुरक्षित

प्रदेश के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात

सीएम योगी आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र

लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र देंगे और 40 खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। रिंकू सिंह, राजकुमार पाल सहित कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर विभिन्न पद दिए जाएंगे, जिससे खेलों को बढ़ावा और युवाओं को प्रेरणा मिलेगी।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार शाम 5 बजे लखनऊ में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस कार्यक्रम में क्रिकेटर रिंकू सिंह और हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल समेत छह खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा, 40 अन्य खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया जाएगा।खेल निदेशक आर.पी. सिंह के अनुसार, अलीगढ़ निवासी रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी (आरएसओ) के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। रिंकू सिंह टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके हैं। वहीं, गाजीपुर के राजकुमार पाल, जो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं, उन्हें पुलिस विभाग में डिप्टी एसपी (डीएसपी) के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा, अन्य खिलाड़ियों को भी उनकी उपलब्धियों के आधार पर विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। नोएडा के प्रवीण कुमार, इटावा के अजीत सिंह और गाजियाबाद के सुमिरन को पंचायती राज विभाग में अधिकारी पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं, मुजफ्फरनगर की रहने वाली प्रीतिपाल को खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के पद पर नियुक्त किया जाएगा।इन खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। पेरिस ओलंपिक में प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अजीत सिंह ने भाला फेंक में रजत पदक और सुमिरन ने 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किया। वहीं, प्रीतिपाल ने पैरा एथलेटिक्स में 100 और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सरकार का यह कदम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और खेलों के प्रति युवाओं में रुचि बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उनकी उपलब्धियों को सम्मान देने पर जोर दिया है। इस कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों को न केवल नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, बल्कि उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। इससे प्रदेश में खेलों के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इस तरह की पहल से युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और वे खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे प्रदेश और देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और ऊंचा होगा।

जीआरपी का सफल अभियान, तकनीकी मदद से फोन बरामद

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

जीआरपी पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोन बरामदगी में बड़ी सफलता हासिल की है। मंगलवार को जीआरपी लखनऊ ने करीब 70 लाख रुपए कीमत के 287 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंप दिए। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने राहत की सांस ली और एसपी रोहित मिश्रा का धन्यवाद करते नजर आए।मोबाइल बरामदगी के लिए जीआरपी की सर्विलांस टीम ने विशेष अभियान चलाया। जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के आधार पर टीमों का गठन किया गया। तकनीकी सहायता से मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक की गई और विभिन्न राज्यों में इस्तेमाल हो रहे मोबाइलों को समन्वय बनाकर बरामद किया गया। बरामद किए गए 287 मल्टीमीडिया मोबाइल अलग-अलग कंपनियों के हैं और इन्हें सुरक्षित रखा गया था।पुलिस लाइन में एसपी रोहित मिश्रा ने मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे। जैसे ही लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल मिले, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने पुलिस का धन्यवाद किया।एसपी रोहित मिश्रा ने बताया कि यह अभियान जनसुनवाई में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर शुरू किया गया था। इसमें तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल कर बड़ी संख्या में मोबाइल बरामद किए गए। इस कार्रवाई से आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।उन्होंने यह भी बताया कि मोबाइल रिकवरी अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक पीड़ितों को उनका खोया सामान वापस मिल सके और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

महिलाओं ने जेवर बेचे, बच्चे अपनी गुल्लक तोड़कर भेज रहे सहयोग, शिया समाज ने दिखाई इंसानियत की मिसाल

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच लखनऊ के दरगाह हजरत अब्बास से आर्थिक मदद ईरान भेजी जा रही है। दरगाह में लगाए गए स्कैनर के माध्यम से बड़ी संख्या में शिया समाज के लोग ईरान को आर्थिक सहायता भेज रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह स्कैनर ईरान एंबेसी से जुड़ा हुआ है। दरगाह में महिलाएं अपने जेवर बेचकर और छोटे बच्चे अपनी गुल्लक तोड़कर मदद पहुंचा रहे हैं। कई महिलाएं भावुक होकर फूट-फूटकर रोती भी नजर आईं। एक महिला ने कहा, "ईरान की हर मदद करूंगी। अपने चारों बेटों को कुर्बान कर दूंगी।" शियाओं ने भी इस बात पर जोर दिया कि उन्हें अपनी बचत और जो कुछ भी संभव हो वह ईरान को देंगे।दरगाह के अध्यक्ष मीसम रिजवी ने बताया कि QR कोड के माध्यम से सीधे ईरान एंबेसी को सहायता भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे भी अपने गुल्लक लेकर आए हैं। "ईरान में हुई बमबारी में शहीद हुए बच्चों की याद में हमारे बच्चे अपना पैसा लेकर आए हैं। फिलहाल कैश भेजने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, और हम ईरान एंबेसी तथा ईरान कल्चरल हाउस से प्रतिनिधि बुलाने की कोशिश कर रहे हैं," उन्होंने कहा। मीसम रिजवी ने यह भी बताया कि ईरान ने हमेशा भारत की मदद की है। उन्होंने कहा कि ईरान ने भारत को गैस और ऑक्सीजन की आपूर्ति की, साथ ही दुनिया में सबसे सस्ता तेल भी उपलब्ध कराया। भारत और ईरान के बीच दोस्ताना संबंधों के कारण लोगों ने इंसानियत और मित्रता के नाते आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है।उन्होंने अमेरिका और इजरायल द्वारा किए जा रहे हमलों का

विरोध भी किया। मीसम की अम्मी, नाज, भी भावुक होकर दरगाह पहुंचीं और कहा कि वह ईरान की मदद के लिए आई हैं। उन्होंने बताया कि ईरान में हालात देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ है और अगर जरूरत पड़ी तो अपने बेटों को कुर्बान करने तक के लिए तैयार हैं। नाज ने कहा, "ईरान को फतह कब मिलेगी नहीं पता, लेकिन हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। हम वहां जा नहीं सकते, इसलिए बच्चों के जरिए मदद भेज रहे हैं।" इस अभियान में शिया समुदाय ने न केवल आर्थिक मदद भेजी बल्कि अपने भावनात्मक समर्थन का भी प्रदर्शन किया, जिससे इंसानियत और आपसी सहयोग की भावना दिखाई दे रही है।

लखनऊ में मौसम साफ

दिन में बढ़े तापमान के बीच सुबह हल्की धुंध

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

मंगलवार को लखनऊ में मौसम साफ बना हुआ है और सुबह से चटक धूप दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर और शाम के समय बादलों की हल्की आवाजाही की संभावना है। आज शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।सोमवार को अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 0.1 डिग्री कम था। अधिकतम आर्द्रता 70 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 34 फीसदी रही।मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 26 से 28 मार्च के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। इसके बाद 29 मार्च से बारिश का असर बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि

अभी चल रहे पश्चिमी विक्षोभ के समाप्त होने के कारण आज दिन का तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री अधिक बढ़ गया है। हालांकि, तापमान अभी भी सामान्य से थोड़ी कम स्थिति में है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि हवा में नमी अधिक होने और वायुमंडल के स्थिर रहने की वजह से सुबह के समय कई जगहों पर हल्की धुंध रह सकती है। अगले 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान में 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा।

राजाजीपुरम की सपना कॉलोनी में बंदरों का आतंक

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के राजाजीपुरम की सपना कॉलोनी के लोग इन दिनों खौफ के साए में जी रहे हैं। यहां बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोग सड़कों पर ही नहीं, अपने घरों के भीतर भी सुरक्षित नहीं हैं। ड्राइंग रूम से लेकर किचन और बेडरूम तक में घुसकर बंदर हमला कर रहे हैं। लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर काट रहे हैं। बच्चों के गाल पर थप्पड़ मारकर उन्हें नोच रहे हैं। दहशत का आलम यह है कि एक युवक डरकर दूसरी मंजिल से कूद गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग अब खुद ही सुरक्षा का इंतजाम करने को मजबूर हैं। किसी ने बालकनी में लोहे का जाल लगवा लिया है, तो कोई लाठी-डंडा लेकर घर से बाहर निकल रहा है। सबसे ज्यादा असर बच्चों पर है। डर के कारण वे मोबाइल या टीवी पर बंदरों की तस्वीर देखकर भी सहम जा रहे हैं। लोगों ने 1076, नगर निगम और वन विभाग में शिकायतें कीं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सपना कॉलोनी की समृद्धि सिंह ने बताया- मैं कमरे में छोटी बच्ची को गोद में खिला रही थी। अचानक बंदर आ गया। उसने हमें धक्का दिया और छोटी बच्ची की तरफ लपका। मैंने बच्चे को किनारे कर दिया। तब तक बंदर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और हाथ नोच लिया। मैं दर्द से चीखने लगी। आवाज सुनकर परिवार के लोग दौड़े और जान बचाई। मुझे फौरन अस्पताल लेकर गए। 7 इंजेक्शन लगे। बंदर ने जब काटा तो असहनीय दर्द हुआ था। अभी भी दर्द हो रहा है। घटना के बाद हम कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं।

जिला प्रशासन ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में एजेंसियों और गोदामों का व्यापक निरीक्षण किया

जिला प्रशासन ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक व्यापक निरीक्षण अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान प्रशासन ने गैस एजेंसियों, गोदामों और वितरण केंद्रों का विस्तृत जायजा लिया, ताकि स्टॉक की स्थिति, वितरण प्रणाली और उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।तहसील बीकेटी में उपजिलाधिकारी कुमार सौरभ और पूर्ति निरीक्षक की टीम ने आधार खेड़ा स्थित जनता कमर्शियल एचपी गैस गोदाम का निरीक्षण किया। वहीं नगरीय क्षेत्रों में अभियान चलाते हुए अलग-अलग टीमों ने आलमबाग, चौक और राजाजीपुरम सहित कई इलाकों में गैस एजेंसियों की जांच की। अधिकारियों का मुख्य फोकस स्टॉक रजिस्टर, बुकिंग रिकॉर्ड और वितरण प्रक्रिया की बारीकी से पड़ताल पर रहा।आलमबाग में टीम-1 के तहत एसीएम-3 अशोक कुमार चौरसिया ने शीला गैस सर्विस और सूरज गैस सर्विस का निरीक्षण किया। टीम-2 ने चौक क्षेत्र में चिराग गैस एजेंसी और जनता एचपी गैस गोदाम की जांच की। वहीं टीम-3 के तहत क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने राजाजीपुरम, पाल तिराहा, तेजा खेड़ा और लाल कोठी क्षेत्र में गैस वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया। सभी स्थानों पर गैस सिलेंडरों की उपलब्धता, वितरण की समयबद्धता और संभावित अनियमितताओं की जांच की गई।निरीक्षण अभियान के दौरान महात्मा गांधी मार्ग (मोती महल रोड) पर एक संदिग्ध दोपहिया वाहन से चार घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। वाहन के चालक की पहचान गौरव यादव, निवासी टीजी हॉस्टल, खदरा के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में मामला गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी से जुड़ा पाया गया। इसके बाद प्रशासन ने तत्काल सख्त कार्रवाई शुरू की।प्रशासन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। जांच टीम में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी परवेज अख्तर और पूर्ति निरीक्षक हर्ष मिश्र भी शामिल रहे। उन्होंने मौके पर

कार्रवाई को अंजाम दिया।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और वितरण में किसी भी तरह की अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में भी इस तरह के निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे, ताकि नागरिकों को समय पर और बिना किसी परेशानी के घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सके।

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर कार्रवाई तेज

4.52 करोड़ बकाया वसूली अभियान शुरू

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं से बकाया बिल वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। लंबे समय से बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन अब ऑटो-कट सिस्टम के जरिए स्वतः काटे जा रहे हैं। विभाग की इस कार्रवाई से शहर के हजारों उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, शहर खंड में कुल 11,232 स्मार्ट मीटर उपभोक्ता पंजीकृत हैं। इनमें से लगभग 9,200 उपभोक्ताओं ने लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। इन पर कुल 4.52 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसे वसूलने के लिए विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) हिमांशु चौधरी ने बताया कि विभाग द्वारा कई बार सूचना देने और भुगतान के लिए चेतावनी जारी करने के बावजूद उपभोक्ताओं ने बकाया नहीं चुकाया। इसके चलते 15 मार्च से उन सभी कनेक्शनों को ऑटो-कट मोड पर डाल दिया गया है, जिन पर 1,000 रुपये से अधिक की देनदारी है। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम पूरी तरह स्वचालित है और बकाया होने पर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिजली आपूर्ति बंद कर देता है। विभागीय जानकारी के मुताबिक, अब तक करीब 700 घरों की बिजली आपूर्ति स्वतः बंद की जा चुकी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और बकाया न चुकाने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के काटे जा सकते हैं। इस बीच, बिजली विभाग ने यह आशंका भी जताई है कि जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन कटे हैं, उनमें से कुछ लोग अवैध तरीके से बिजली चोरी का प्रयास कर सकते हैं। इसे रोकने के लिए विजिलेंस टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। ये टीमें घर-घर जाकर जांच कर रही हैं कि कहीं कटे हुए कनेक्शनों पर अवैध रूप से बिजली का उपयोग तो नहीं हो रहा। विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि बिजली चोरी करते हुए कोई पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि स्मार्ट मीटर को प्री-पेड प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया जुलाई 2025 से शुरू की गई थी। इस प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को पहले रिचार्ज कराना होता है, तभी बिजली आपूर्ति जारी रहती है। हालांकि, कई उपभोक्ता समय पर रिचार्ज नहीं करा रहे हैं, जिससे उनकी बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है।साथ ही, उपभोक्ताओं को तकनीकी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में ऑनलाइन भुगतान करने के बावजूद बिजली बहाल होने में 24 घंटे तक का समय लग रहा है। इसके अलावा, कुछ उपभोक्ताओं ने यह शिकायत भी की है कि भुगतान की राशि रिफंड हो जाने के कारण उन्हें बिजली उपकेंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। एक्सईएन हिमांशु चौधरी ने बताया कि विभाग इन तकनीकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे समय पर अपने बिजली बिल का भुगतान करें और उपभोक्ता ऐप या स्मार्ट कंज्यूमर ऐप के माध्यम से रिचार्ज करते रहें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। बिजली विभाग की इस सख्ती को देखते हुए स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में बकाया बिल न चुकाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई और तेज हो सकती है।

उन्नाव के सहजनी चौराहे पर भीषण सड़क हादसा

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सहजनी चौराहे पर सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद डम्पर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शी दीपक के अनुसार, चौराहे के पास कुछ लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर नाश्ता कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार से आए एक डम्पर चालक ने नियंत्रण खो दिया और खड़ी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सुभाष कुमार जायसवाल (40) निवासी अटवा चकलवंशी, थाना माखी की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी रत्ना जायसवाल गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें आसपास के लोगों की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि डम्पर चालक नशे की हालत में था और अत्यधिक तेज गति से वाहन चला रहा था। टक्कर मारने के बाद वह वाहन लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि फरार डम्पर ने आगे करोवन मोड़ पर भी एक अन्य वाहन को टक्कर मारी, जिसमें एक और व्यक्ति की मौत की सूचना है। स्थानीय लोगों ने बताया कि चौराहे पर हाल ही में स्पीड ब्रेकर बनाया गया था और सड़क की स्थिति भी ठीक थी। ऐसे में हादसे का मुख्य कारण चालक की लापरवाही और नशे में वाहन चलाना माना जा रहा है। लोगों ने क्षेत्र में बढ़ती तेज रफ्तार और शराब पीकर वाहन चलाने की घटनाओं पर चिंता जताई है। घटना की सूचना पर गंगाघाट कोतवाली के इंस्पेक्टर अजय सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार चालक की तलाश में आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्नाव में गैस एजेंसी बंद, उपभोक्ताओं ने हाईवे जाम किया

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

नवाबगंज कस्बे में गैस सिलेंडर वितरण में लगातार हो रही लापरवाही और भैया जी गैस एजेंसी के अचानक बंद होने से नाराज उपभोक्ताओं ने मंगलवार को कानपुर-लखनऊ हाईवे जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर गैस सिलेंडर रखकर विरोध जताया, जिससे हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह से ही बड़ी संख्या में उपभोक्ता गैस सिलेंडर लेने एजेंसी पहुंचे थे, लेकिन एजेंसी बंद मिली। घंटों इंतजार के बावजूद न तो कोई कर्मचारी मौके पर पहुंचा और न ही गैस वितरण शुरू किया गया। इससे नाराज होकर उपभोक्ताओं का धैर्य टूट गया और उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एजेंसी लगातार लापरवाही बरत रही है। उपभोक्ताओं के अनुसार, 10-10 दिनों तक गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाती, जबकि मोबाइल फोन पर 'डिलीवर्ड' होने का संदेश भेज दिया जाता है। शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। हाईवे जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। नवाबगंज चौकी इंचार्ज मुकुल दुबे ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। पुलिस की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम समाप्त कर दिया, जिसके बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो सका।जाम के चलते राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर विवाद सामने आया है।बताया जा रहा है कि इससे पहले 19 मार्च को भी इसी गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार और कम गैस देने का मामला सामने आया था। उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एजेंसी संचालक को माफी मांगनी पड़ी थी। लगातार सामने आ रही शिकायतों से उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों ने जिला प्रशासन से गैस वितरण व्यवस्था की गहन जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याएं दोबारा न हों।

गंगाघाट नगर पालिका का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं में सुधार के दिए निर्देश

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

एससी-एसटी आयोग के सदस्य एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रमेश चंद ने मंगलवार को गंगाघाट नगर पालिका परिषद का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली, साफ-सफाई व्यवस्था, जनशिकायतों के निस्तारण और विकास कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की।मंत्री के अचानक निरीक्षण से नगर पालिका कार्यालय में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। कर्मचारी और अधिकारी तत्काल सक्रिय हो गए। निरीक्षण की शुरुआत उन्होंने कार्यालय परिसर की साफ-सफाई और अभिलेखों के रखरखाव की जांच से की। उन्होंने रिकॉर्ड रजिस्टर, शिकायत पत्रों और उनके निस्तारण की स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया।रमेश चंद ने अधिकारियों से लंबित शिकायतों की संख्या और उनके समाधान में हो रही देरी के बारे में सवाल किए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आम जनता की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर और तय समय सीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेना प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने नगर क्षेत्र में चल रहे सफाई अभियान, कूड़ा उठान व्यवस्था और नालों की सफाई की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसका सीधा संबंध लोगों के स्वास्थ्य से है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि सफाई व्यवस्था में ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।मंत्री ने नगर पालिका में उपस्थित नागरिकों से भी बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं। कई लोगों ने जल निकासी की समस्या, खराब सड़कों और नियमित सफाई न होने की शिकायत की। इस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने और समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि शासन की मंशा है कि योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के अंत में नगर पालिका अधिकारियों ने मंत्री को आश्वस्त किया कि सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जल्द ही नगर में साफ-सफाई, शिकायत निस्तारण और विकास कार्यों में सुधार देखने को मिलेगा।

उन्नाव में कोतवाली क्षेत्र के पास तीन दुकानों में चोरी

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। कोतवाली के ठीक बगल में स्थित तीन अस्थायी दुकानों में चोरी की वारदात हुई है। चोर की यह हरकत पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। यह घटना चैत्र नवरात्रि के दौरान हुई, जब पूजा सामग्री, फूल-माला और श्रृंगार से संबंधित अस्थायी दुकानें लगाई गई थीं। देर रात अज्ञात चोर ने मौके का फायदा उठाते हुए एक-एक कर इन तीन दुकानों को निशाना बनाया। चोर दुकानों से नकदी, नारियल, चुनरी, लाई और श्रृंगार सामग्री सहित हजारों रुपये का सामान चुरा ले गया। पीड़ित दुकानदार रानी गुप्ता ने बताया कि उन्होंने रोजाना की तरह रात में दुकानों को प्लास्टिक तिरपाल से ढककर घर चली गई थीं। सुबह करीब तीन बजे आसपास के लोगों को कुछ आहट महसूस हुई, लेकिन तब तक चोर वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुका था। सुबह जब दुकानदार पहुंचे, तो सामान बिखरा मिला और नकदी सहित कई जरूरी वस्तुएं गायब थीं। वहीं, दूसरे दुकानदार रमेश सैनी ने भी अपनी दुकान से नकदी और पूजा सामग्री चोरी होने की जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोतवाली के पास ही चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था की कमी को दर्शाता है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक युवक दुकान के पास आकर तिरपाल हटाकर सामान चोरी करते हुए स्पष्ट दिख रहा है। फुटेज में आरोपी आराम से वारदात को अंजाम देता नजर आ रहा है, जिससे साफ है कि उसे पुलिस गश्त का कोई डर नहीं था।

मिशन शक्ति अभियान के तहत पॉलिटेक्निक कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम

मिशन शक्ति फेज-5.2 अभियान के तहत मंगलवार को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, डीह में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। यह आयोजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उन्नाव के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी लाइन विनी सिंह तथा थाना कोतवाली सदर की मिशन शक्ति टीम ने सक्रिय भागीदारी की। उन्होंने छात्राओं को महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं, संवैधानिक अधिकारों, आत्मरक्षा के उपायों और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की स्थिति में सहायता प्राप्त करने के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान पुलिस टीम ने विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की उपयोगिता पर विशेष जोर दिया। छात्र-छात्राओं को 1090 (वूमेन पावर लाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 102 और 108 (स्वास्थ्य सेवाएं) तथा 1930 (साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन) के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें सलाह दी गई कि किसी भी आपात स्थिति या संदिग्ध परिस्थिति में इन नंबरों का तुरंत उपयोग करें। कार्यक्रम में डिजिटल सुरक्षा और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग पर भी विशेष चर्चा की गई। अधिकारियों ने बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने और सही जानकारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा, छात्रों को समाज में महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार अपनाने का संदेश भी दिया गया। कॉलेज के प्रधानाचार्य चंद्रभान सिंह ने पुलिस टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम छात्रों में जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की आवश्यकता पर जोर दिया।कार्यक्रम के सफल संचालन में प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र डॉ. आशीष श्रीवास्तव की अहम भूमिका रही। इस अवसर पर महिला उपनिरीक्षक रेखा देवी, महिला कांस्टेबल दुर्गेश, सर्वेश, प्रिया, कांस्टेबल अंकेश यादव और मानवेंद्र सिंह सहित मिशन शक्ति टीम के सदस्य उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी अतुल वत्स का निर्देश

अवशेष निर्माण कार्य जल्द और गुणवत्तापूर्वक पूरे करें

टीवी भारतवर्ष हाथरस

जिलाधिकारी ने जनपद में 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा नवीन आश्रम पद्धति मऊ चिरायल निर्माण कार्य, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम अलीगढ़ द्वारा जिला चिकित्सालय हाथरस में 50 बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कार्य, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड आगरा द्वारा जनपद हाथरस के विकासखंड हाथरस में पैक्स हाथरस जंक्शन का 250 मेट्रिक टन गोदाम का निर्माण कार्य, जनपद हाथरस से तहसील सासनी के ग्राम नगला गढ़ू में गो-संरक्षण केंद्र का निर्माण कार्य, नगर पालिका परिषद हाथरस द्वारा तालाब चौराहा स्थित तालाब का सौंदर्यकरण, स्वेज फार्म की भूमि पर जलेसर रोड के सहारे 133 दुकानों के व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण कार्य, सीवेज फार्म स्थित पालिका के स्वामित्व की भूमि पर कान्हा गौशाला पशु शेल्टर होमस् का निर्माण कार्य, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड निर्माण प्रखंड अलीगढ़ द्वारा जनपद हाथरस में खेल अवस्थपनाओं के जीणोद्धार इत्यादि के निर्माण कार्य, उ0प्र0 जल निगम नगरीय हाथरस द्वारा पुरदिल नगर पंचायत पेयजल योजना, नगर पंचायत सादाबाद पेयजल योजना का निर्माण कार्य, नगर पालिका परिषद सिकंद्राराऊ पेयजल योजना, 24×7 नगर पालिका परिषद हाथरस आवास विकास वाटर सप्लाई स्कीम निर्माण कार्य, यूनिटयूनिट 25 सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम अलीगढ़ द्वारा जनपद हाथरस के मुरसान में कंचना सरोवर के पर्यटन का विकास कार्य, तहसील सादाबाद ग्राम एदलपुर में स्थित श्री दाऊजी महाराज मंदिर का पर्यटन विकास कार्य, जनपद हाथरस के उदयसिंह की कचहरी, सासनी हाथरस लैंडस्कैपिंग, पाथवे, जन सुविधा चहारदीवारी एवं सोलर प्रकाश व्यवस्था के कार्य, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड निर्माण इकाई 32 अलीगढ़ द्वारा जनपद हाथरस विकासखंड सिकंदराराऊ के ग्राम गंगागढ़ी स्थित मंदिर हनुमान गढ़ी का पर्यटन विकास कार्य, जिला योजना अंतर्गत जनपद हाथरस के विकासखंड सासनी के ग्राम थौरपुर में स्थित काली माई मंदिर का पर्यटन विकास कार्य, विकास खंड सादाबाद के ग्राम पंचायत नगला राम राम के ढकपुरा मंदिर (स्वर्ग आश्रम) का पर्यटन का विकास कार्य, जनपद हाथरस के विकासखंड सदर में खिटौली से परौली के बीच स्थित प्राचीन सिद्धपीठ परासर तपोभूमि का पर्यटन का विकास कार्य, लोक निर्माण विभाग भवन खंड अलीगढ़ द्वारा नवीन जिला कारागार के भवन का निर्माण कार्य, जनपद हाथरस में मा0 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बर्दवारी का निर्माण कार्य, ग्राम अभिकरण विकास विभाग हाथरस द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हसायन में एकेडमिक ब्लॉक एवं हॉस्टल भवन का निर्माण कार्य, सरस्वती इंटर कॉलेज हाथरस में कक्षा-कक्षों की मरम्मत का कार्य, लोक निर्माण विभाग हाथरस द्वारा जनपद हाथरस में ट्रांजिस्ट हॉस्टल (16 यूनिट) का निर्माण कार्य (जी0+3) निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबधित कार्यदायी संस्थाओं को लम्बित निर्माण कार्यों को निर्धारित समयावधि के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं से कहा कि यदि किसी भी प्रकार की कहीं पर समस्या आ रही है तो उसे अवगत करायें, जिससे कि समय रहते हुए उस समस्या का समाधान किया जा सके, लापरवाही पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला स्पोटर्स अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग/जल निगम तथा अन्य संबंधित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था प्रभारी आदि उपस्थित रहे।

ब्यूरो चीफ दुष्यंत पचौरी हाथरस

वाराणसी में सिलेंडर ब्लास्ट से मकान ढहा, भाई-बहन की मौत

टीवी भारतवर्ष वाराणसी

वाराणसी के लहरतारा इलाके में मंगलवार सुबह करीब साढ़े 7 बजे एक भयानक हादसा हुआ, जब घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फट गया। धमाके से पूरा मकान भराभराकर ढह गया। हादसे के समय घर में मां गिरिजा देवी (60) और उनके तीन बच्चे—ओम कुमार चौधरी (31), अमन चौधरी (33) और बेटी प्रीति उर्फ लक्ष्मी (28)—मौजूद थे।धमाके के तुरंत बाद पड़ोसी दौड़े और मदद के लिए पहुंचे। मकान मलबे में दबे लोगों को पुलिस और दमकल की टीम ने बाहर निकाला। चारों को तत्काल बीएचयू ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने ओम और प्रीति को मृत घोषित कर दिया। वहीं, मां गिरिजा देवी और बड़ा बेटा अमन गंभीर रुप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। घटना काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 7 किलोमीटर दूर हुई। हादसे का मुख्य कारण सिलेंडर से गैस लीक होना और पाइप में आग लगना बताया जा रहा है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के कई मकानों में दरारें आ गईं और लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय लोग बताते हैं कि मकान करीब 50 साल पुराना था। पीछे का हिस्सा हाल ही में बनवाया गया था और आगे का हिस्सा जर्जर था, जहां सभी लोग मौजूद थे। घर में सिलेंडर ब्लास्ट से पहले गैस का रिसाव हुआ और आग फैल गई।मौके पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने जेसीबी की मदद से मलबा हटाना शुरू किया। डीआईजी शिवहरि मीणा और एडीसीपी वरूणा जोन नीतू कादयान ने घटनास्थल का मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम ने सिलेंडर को जांच के लिए भेज दिया है।पड़ोसियों ने बताया कि धमाके की आवाज सुनकर वे दौड़े और मदद के लिए जुट गए। हादसे ने इलाके में दहशत फैलाई है और लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

विश्व हिंदू महासंघ अलीगढ़ (हरीगढ़), उ0प्र द्वारा

व्यस्तम चौराहे का नाम "वंदे मातरम् चौक" रखने हेतु जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया

टीवी भारतवर्ष अलीगढ़

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की मंशा के अनुरूप "वंदे मातरम्" गीत की 151वीं वर्षगांठ तथा 23 मार्च को शहीद-ए-आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के 95वें शहादत दिवस के पावन अवसर पर विश्व हिन्दू महासंघ, उत्तर प्रदेश की जिला अलीगढ़ इकाई व्यस्तम चौराहे का नाम "वंदे मातरम् चौक" रखने की मांग करती है।महोदय, लोकसंन्यासी योगी जी महाराज का मानना है कि "वंदे मातरम्" केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। इसके प्रति भारतीयों की श्रद्धा सर्वविदित है। वंदे मातरम् के उद्घोष ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नौजवानों के मन में ऐसा जोश और उत्साह उत्पन्न किया कि वे हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूमने के लिए भी तैयार हो जाते थे। आज भी वंदे मातरम् का उद्घोष देशवासियों के मन में अद्भुत ऊर्जा, देशभक्ति और समर्पण का भाव उत्पन्न जिसमें सोनू कुमार जिलाध्यक्ष, अरविन्द लोधी महानगर अध्यक्ष, संदीप कुशवाह प्रदेश अध्यक्ष गोरक्षा प्रकोष्ठ, छोटे लाल मंडल प्रभारी, राजीव मित्तल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वीकेश कुमार जिला प्रभारी, मुकुल वशिष्ठ, वंशी वर्मा, राहुल प्रजापति, आशीष वाल्मीकि, सतेंद्र चौधरी, सोनू चौधरी, ऋषिपाल चौधरी, शिव लहरी, महेश बघेल, मुकुल वाल्मीकि, हरीश लोधी, अमित वाल्मीकि एवं जिला , महानगर तहसील, ब्लॉक एवं सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मोहन भागवत ने मथुरा में अवैध प्रवासियों और तीन संतान नीति पर की अहम टिप्पणियां

टीवी भारतवर्ष मथुरा

मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मंगलवार को अवैध प्रवासियों और जनसंख्या नीति को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। वृंदावन के रुक्मिणी विहार स्थित नव-निर्मित 'जीवनदीप आश्रम' के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि संदिग्ध अवैध प्रवासियों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें देश में रोजगार न मिले।भागवत ने अमेरिका और चीन जैसे देशों की 'आक्रामक' प्रवृत्ति की निंदा करते हुए भारत को अन्य दृष्टिकोणों के प्रति अधिक उदार बताया। उन्होंने कहा कि विदेशियों की पहचान के लिए कड़ी जांच होनी चाहिए, लेकिन भारतीय नागरिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि यदि ऐसे उपाय लागू किए जाएं, तो पांच से दस वर्षों में स्थिति में सुधार संभव है और घटती जन्म दर को स्थिर किया जा सकता है।इस अवसर पर भागवत ने तीन संतान नीति पर जोर देते हुए कहा कि अस्तित्व बचाने और सामाजिक संतुलन के लिए प्रत्येक परिवार में कम से कम तीन बच्चे होना जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर भी परिवारों को तीन बच्चों की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे बचपन में मेलजोल और सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। भागवत ने कई जनसंख्या संबंधी अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा कि तीन से कम प्रजनन दर दीर्घकालिक जोखिम पैदा कर सकती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कम जन्म दर वाले कई देशों ने इसे बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं।संघ प्रमुख ने जबरन धर्मांतरण रोकने का आह्वान किया और कहा कि सरकार कानून बना सकती है, लेकिन समाज को भी इसे रोकने की जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अनेक धर्मांतरित लोग मूल रूप से हिंदू थे और यदि वे वापस आना चाहते हैं, तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए।भागवत ने भारत के प्राचीन सांस्कृतिक मूल्य और सनातन परंपरा पर भी प्रकाश डाला, कहा कि ये आज की 'अशांत दुनिया' में भी प्रासंगिक हैं और आश्रम इन मूल्यों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।